कांग्रेस ने वैसे तो कई गलतियां की, लेकिन हार की सबसे बड़ी वजहें यह रहीं

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने वंशवाद को बढ़ावा दे रहे नेताओं पर हमला बोला, राहुल के इस रुख की सराहना हो पाती उससे पहले ही कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने इस बात का खंडन कर दिया कि राहुल ने कार्यसमिति की बैठक में ऐसा कुछ नहीं कहा।

लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई। लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि पार्टी संसद में मुख्य विपक्ष का दर्जा हासिल करने लायक भी सीटें नहीं जीत पाई। कांग्रेस कार्यसमिति ने हार के कारणों पर चर्चा करने और जिम्मेदारी तय करने को लेकर एक बैठक भी की लेकिन इस बैठक से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। बैठक से पहले कहा गया कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे लेकिन उन्होंने जो इस्तीफा देने का प्रस्ताव किया उसे सर्वसम्मति से ठुकरा दिया गया। बाद में यह खबर आई कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने वंशवाद को बढ़ावा दे रहे नेताओं पर हमला बोला, राहुल के इस रुख की सराहना हो पाती उससे पहले ही कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने इस बात का खंडन कर दिया कि राहुल गांधी ने कार्यसमिति की बैठक में ऐसा कुछ नहीं कहा।

हिन्दू तो बन गये

2014 का लोकसभा चुनाव जब कांग्रेस हारी थी तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हार की समीक्षा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश की बहुसंख्यक आबादी हिन्दुओं को लगा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है इससे वह पार्टी से दूर हो गये। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला तो एंटनी समिति के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए जनेऊ धारण किया और चल पड़े मंदिरों की यात्रा पर। इसका फल भी मिला जब गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी ने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया। खुद को शिवभक्त बताने वाले राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर भी गये और कैलाश मानसरोवर भी गये। यही नहीं लोकसभा चुनावों तक जिस राज्य में वह चुनाव प्रचार करने जाते थे वहां अकसर मंदिरों में पूजा अर्चना करते देखे गये। यही नहीं 2019 के चुनावों में राजनीति में पदार्पण करने वाली उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मंदिरों और मजारों पर लगातार गयीं। अब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस आलाकमान एंटनी समिति की दिखाई राह पर आगे बढ़ रहा था तब गलती कहाँ हुई ?

मगर राष्ट्रवादी नहीं बन सके

कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि वह राष्ट्रवाद का माहौल बनाकर विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने में सफल रही लेकिन देखिये यहीं कांग्रेस से सबसे बड़ी गलती हुई है। देश पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अलग सुर अलापती नजर आई और जनता ने उसे ठुकरा दिया। कांग्रेस से गलती सिर्फ चुनावों के वक्त हुई, ऐसा नहीं है। 2016 में जब उरी हमला हुआ और भारतीय सेना ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया तब कांग्रेस ने सेना के शौर्य के सुबूत मांगकर पहली गलती की। कांग्रेस ने चुनावों से पहले सरकार से बार-बार सर्जिकल स्ट्राइक के सुबूत मांगे और चुनावों के वक्त कह दिया कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। कांग्रेस के अलग-अलग नेता सर्जिकल स्ट्राइक की अलग-अलग संख्या बताते रहे और अपने कार्यकाल के सुबूतों की चर्चा तक नहीं की। बाद में सेना की ओर से साफ किया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार उरी हमले के बाद ही की गयी थी।

कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के सुबूत मांगकर अपनी पिछली सरकारों की कथनी और करनी पर भी लोगों की नजरें आकर्षित कर दीं। जब यह बात सामने आई कि मुंबई हमले के दौरान वायुसेना ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि सीमापार जाकर कार्रवाई की जाये तो उस समय सेना और वायुसेना को रोक दिया गया था, इससे भी कांग्रेस की चुनावों के दौरान किरकिरी हुई। इसके अलावा पुलवामा हमले के बाद बालाकोट पर की गयी भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को पहले तो कांग्रेस ने सराहा लेकिन कुछ दिनों बाद ही वायुसेना से भी सुबूत मांगकर गलती कर दी। कांग्रेस मोदी विरोध की राह में बढ़ते-बढ़ते कब देशविरोधी दिखने लग गयी इसका अहसास शायद उसे हुआ नहीं होगा इसीलिए उसने देशद्रोह को परिभाषित करने वाली धारा 124 (ए) को खत्म करने का वादा अपने चुनाव घोषणापत्र में कर डाला। इस मुद्दे ने तो जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का काम ही कर डाला। सारे देश में एक माहौल बन गया कि कांग्रेस देशद्रोहियों को बचाना चाहती है।

पिछली गलतियों से नहीं लिया सबक

कांग्रेस भूल गयी कि ऐसी ही गलती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान उसने 1999 में तब की थी जब चुनावों से ठीक पहले कारगिल की लड़ाई चल रही थी तब पार्टी नेता सरकार के खुफिया तंत्र की विफलता और सरकार के निद्रा में लीन होने का आरोप लगाते रहे। लेकिन देश और दुनिया देख रही थी कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर तक बस की यात्रा करके दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के प्रयास किये थे। कारगिल में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ वाजपेयी सरकार की कोई ढिलाई नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की ओर से पीठ में घोंपा गया छुरा था।

राफेल पर बेकार का हौवा खड़ा किया

कांग्रेस के कार्यकाल में लगभग हर छोटा-बड़ा रक्षा सौदा विवादों में रहा शायद इसीलिए पार्टी ने राफेल विमान खरीद में भ्रष्टाचार की बात उठाते हुए अपने आरोप सीधे प्रधानमंत्री पर लगाये। लेकिन उच्चतम न्यायालय भी इस मामले पर अपना फैसला सुना चुका है और जो समीक्षात्मक याचिकाएं दायर की गयी हैं उस पर भी फैसला आने वाला है। रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार का तानाबाना बुन कर चौकीदार को चोर कह तो दिया गया लेकिन चुनावों के बीच में जिस तरह चौकीदार को चोर कहने के लिए माफी मांगनी पड़ी उससे भी साफ हो गया कि कांग्रेस इस अति आधुनिक विमान की भारत को आपूर्ति में बाधा पैदा करने का खेल खेल रही है। यही नहीं गोवा के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मनोहर परिकर को भी राहुल गाहे-बगाहे राफेल मामले में घसीटते रहे जिससे उनकी छवि खराब हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कांग्रेस भले गंभीर पार्टी हो लेकिन चुनाव जीतने के लिए उससे लगातार ऐसी गलतियां होती चली गयीं जिनसे पार्टी बचती तो शायद स्थिति दूसरी होती।

मंथन

चर्चा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते है। लगातार दूसरी पराजय के मंथन से बच निकलने का यह सबसे आसान तरीका है। क्योंकि नया अध्यक्ष गांधी परिवार का वृपापात्र ही होगा। जैसी स्थिति यूपीए सरकार में मनमोहन सिह की थी, वैसी ही दशा कांग्रेस संगठन में गैर गांधी अध्यक्ष की होगी। जब राहुल गांधी ही अघोषित रूप से शीर्ष नेता होंगे, तो अध्यक्ष पद में बदलाव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऐसे में कांग्रेस की भलाई के लिए राहुल को स्वयं में बदलाव लाना होगा। इसके लिए उन्हें आत्मचिंतन करना होगा। इस पर विचार करना होगा कि पांच वर्ष में उनके नरेंद्र मोदी विरोधी सभी मुद्दे औंधे मुंह क्यों गिरे। उन्होंने तो मोदी को चोर, दलाल, खून की दलाली करने वाला, गरीबों की जेब काटने वाला, पन्द्रह पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला, माल्या, नीरव को पैसा देकर भगाने वाला आदि न जाने क्या क्या कहा। इस हिसाब से तो भाजपा का सफाया हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राहुल को इसी विषय पर विचार करना चाहिए।

क्या यह सही नहीं कि उनके मुद्दों ने कांग्रेस का ही नुकसान किया, मोदी की चोर बताने से लोगों ने राहुल की पार्टी को ईमानदार नहीं मान लिया। इन सभी मुद्दों को मर्यादा विहीन माना गया। जिस मोदी ने समाज व राष्ट्र की सेवा के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया, उसके लिए चोर चोर का नारा लगवाना घृणित था, वह भी तब जब इसके कोई प्रमाण राहुल के पास नहीं थे। उन्होंने प्रांस के राष्ट्रपति का नाम लेकर गलत बयानी की, फ्रांस ने इसका खंडन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर गलत बयानी की, इसके लिए फटकार लगी। मोदी के बारे में जो इंटरव्यू राहुल ने दिया, उसमें भी मर्यादा का अभाव था।

राहुल कह रहे थे कि मोदी जी खत्म हो गए, इसके पहले राहुल कहते थे कि मोदी उनकी आंख में आंख डाल कर बात नहीं कर सके। जबकि लोकसभा में मोदी ने राहुल को जो जबाब दिया था, उसमें राहुल को नजर छुपानी पड़ रही थी। फिर भी राहुल नहीं माने। अपने भाषणों में यही दोहराते रहे। आखिर राहुल कौन से तपस्वी राजनेता है, जिनकी आंख में आंख डाल कर बात करना संभव नहीं। राहुल कहते रहे कि मोदी जी गरीबों की नहीं अमीरों की सुनते है, जबकि हम गरीबों की सुनते है। अब राहुल आत्मचिंतन करें कि क्या उनकी इस बात पर आमजन ने विश्वास किया।

पांच वर्ष पहले नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुआ था, फिर भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन्हें जनादेश को स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस अपनी व्याबुलता को कभी छिपा नहीं सका। यही कारण था कि उसके मोदी विरोधी मुद्दों में सिद्धांत की जगह बदनीयत ज्यादा थी। पिछले पांच वर्ष में विपक्ष जमीनी मुद्दों का निर्धारण ही नहीं कर सकी। उसने असहिष्णुता के मुद्दे को हवा दी,इसे अभियान का रूप दिया। इसके तहत सम्मान वापसी होने लगी, फिर ललित मोदी का मुद्दा उठाया, सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग पर संसद ठप्प कर दी, राफेल पर नरेंद्र मोदी को चोर बताया, पन्द्रह लाख रुपए के लिए विपक्ष का प्रत्येक नेता परेशान दिखाई दिया, नोटबन्दी को आर्थिक बर्बादी का कारण कहा, जीएसटी को गब्बर सिह टैक्स बताया, सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया, सबूत मांगे, वुछ नेताओं ने तो पुलमावा हमले को पूर्व निर्धारित साजिश बताया, फिर कहा कि एयर स्ट्राइक के लिए सेना की तारीफ करेंगे, नरेंद्र मोदी की नही, जब जब भाजपा कहीं जीती ईवीएम पर हमला बोला, आदि। जाहिर है कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ सदैव नकारात्मक मुद्दे ही उठाता रहा, यह सब विपक्ष की विश्वसनीयता को कमजोर करने वाले साबित हुए।

अंततः जनता की अदालत में ये सभी मुद्दे खारिज हो गए। इतना ही नहीं ये सभी मुद्दे विपक्ष की फजीहत कराने वाले साबित हुए। असिष्णुता अभियान भी सोची समझी रणनीति के तहत चलाया गया। इसके सूत्रधार वह लोग थे जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश छोड़ने की बात कर रहे थे। अनेक विपक्षी नेता भारत विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन में पहुंच गए थे। धीरे धीरे असहिष्णुता की कलई खुल गई, ये लोग केवल मोदी के प्रति असहिष्णु थे। पन्द्रह लाख रुपए के लिए विपक्ष के नेता ही लालची दिखाई दिए। यह आवाज जनता की तरफ से नहीं उठी थी, न कभी मोदी ने खातों में पन्द्रह लाख रुपए देने की बात कही थी। उन्होंने यही कहा था कि विदेशों में इतना कला धन जमा है, जिससे प्रत्येक नागरिक को पन्द्रह लाख रुपए मिल सकते है। यह रुपए की मात्रा बताने का प्रतीक मात्र था। विपक्षी नेताओं ने बदनीयत में इसे मुद्दा बना दिया। इसी तरह नोटबन्दी, जीएसटी पर उनके विलाप से आमजन प्रभावित नहीं हुआ।

विजय माल्या, नीरव मोदी आदि कांग्रेस के समय बैंकों से कर्ज लेकर राजा बाबू बने थे। उन्हें रोकने का कोई कानून नहीं था। फिर भी वह जितना कर्ज लेकर भागे थे उससे ज्यादा की उनकी संपत्ति मोदी सरकार ने जब्त कर ली। ऐसे में माल्या , नीरव को भगा देने के आरोप से कांग्रेस की छवि ही खराब हुई। मोदी सरकार ने आर्थिक भगोड़ा हेतु बहुत सख्त कानून बना दिये है। अब ऐसे लोगों का कानून के शिवंजे में आना तय है। विपक्ष ने किसानों के आंदोलन के नाम पर सब्जी, फल, दूध के टैंकर सड़कों पर बिखेर दिए। बाद में उजागर हुआ कि ये किसान ही नहीं थे। ऐसे में विपक्ष के सभी मुद्दे उसी पर भारी पड़ गए।

राफेल पर चौकीदार को चोर बताने का कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। राहुल गांधी बिना किसी प्रमाण के यह नारा लगवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी उन्होंने सबक नहीं लिया। वह खुद पेरोल पर रहकर दूसरे को चोर बता रहे थे। इस मुद्दे ने कांग्रेस को ही कटघरे में पहुंचा दिया था। यही कारण था कि आम चुनाव में विपक्ष को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। खेल विकास का मुद्दा चला।

इसमें नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। राजग के आंकड़ा सीढ़े तीन सौ पर पहुंच गया। भाजपा ने अकेले तीन सौ पार किया। आधा दर्जन से अधिक राज्यों में भाजपा ने शत प्रतिशत सीटें जीत ली। डेढ़ दर्जन राज्यों में राजग ने पचास पचास प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किये।

उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बड़ी दम भर रहा था, यहां भाजपा ने लगभग पचास प्रतिशत वोट हासिल किये। वहीं बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वोट प्रतिशत ऐसा ही था। आजादी के बाद से अब तक के चुनावों में किसी एक पाटा ने सबसे ज्यादा लगभग अड़तीस प्रतिशत वोट पहली बार सहानिभूति लहर में राजीव गांधी को मिले थे। इस बार भाजपा विकास के नाम पर करीब वहां तक पहुंच गईं। सत्रह राज्यों व वेंद्र शासित प्रदेशों में पचास उसे पचास प्रतिशत वोट मिले। राजग के विपरीत यूपीए सौ के भीतर ही सिमट गया। जाहिर है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी के विकास और गरीबों के कल्याण हेतु लागू की गईं योजनाओं असर देख ही नहीं सका।